



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 8, 2013/वैशाख 18, 1935

No. 98]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 8, 2013/VAISAKHA 18, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2013

विषय : चीनी ताइपेई तथा यूएसए के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'फेनोल' के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरुआत।

सं. 14/17/2012-डीजीएडी.-समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क व आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे एतदपश्चात पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) के अनुसार मै. हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि. (जिसे एतदपश्चात 'याचिकाकर्ता' अथवा 'आवेदक' कहा गया है) ने चीनी ताइपेई तथा यूएसए (जिन्हें एतदपश्चात संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फेनोल (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत हेतु निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन (जिसे याचिका भी कहा गया है) दायर किया है। मै. हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि. ने संगत सूचना प्रदान की है।

विचाराधीन उत्पाद

2. मौजूदा याचिका और प्रस्तावित जांच में विचाराधीन उत्पाद 'फेनोल' है। फेनोल सामान्यतः सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत एक मूल कार्बनिक रसायन है। उत्पाद का विपणन दो रूपों बल्क और पैकड में किया जाता है। बल्क बिक्री आम तौर पर खुले रूप में होती है जबकि पैकड परेबण अत्यंत कम कंटेनर भार और सामान्यतः ड्रमों में पैक करके किए जा सकते हैं। फेनोल का उपयोग फेनोल फॉर्मलिन्हाइड रेजिनो, लेमिनेटों, प्लाईवुड, गत्ता, विस्फेनोल-ए, अलकाइल फेनोल, मेथज, डाइफिनायल आक्साइड आदि में किया जाता है। यह उत्पाद सीमा-शुल्क टैरिफ शीर्ष सं. 2907 11 10 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि उक्त सीमा-शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तुएं

3. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तु, जिसका निर्यात संबद्ध देशों द्वारा भारत को किया जाता है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तथा संबद्ध देशों से आयातित फेनोल भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया तथा प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं के संबंध में तुलनीय है। उपभोक्ता इन दोनों उत्पादों को एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग में ला सकते हैं। ये दोनों वस्तुएं तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए इन्हें पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित वस्तु के 'समान वस्तु' माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग एवं आधार

4. यह आवेदन मै0 हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि0 द्वारा दायर किया गया है। एक अन्य घरेलू उत्पादक मै0 एसआई ग्रुप ने आवेदन का समर्थन किया है। यह नोट किया जाता है कि आवेदक और समर्थक देश में संबद्ध वस्तु का सम्पूर्ण भारतीय उत्पादन करते हैं। यह भी नोट किया जाता है कि भारत में उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन में याचिकाकर्ता का एक प्रमुख हिस्सा है। यह भी नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने न तो विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है और न ही वह विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक अथवा निर्यातक से संबंधित है। अतः यह निर्धारित किया जाता है कि यह आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किया गया है और आवेदन पाटनरोधी नियमों के नियम 5 के अंतर्गत 'आधार' संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है। इसके अलावा, आवेदक पाटनरोधी नियमों के नियम 2(ख) के अनुसार 'घरेलू उद्योग' है।

संबद्ध देश

5. वर्तमान जांच में शामिल देश चीनी ताइपेई तथा यूएसए हैं।

सामान्य मूल्य

6. याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि संबद्ध देशों के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की कीमत के संबंध में सूचना/साक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। अतः याचिकाकर्ता ने कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमत, घरेलू उद्योग के सर्वोत्तम खपत मानक तथा समुचित लाभ मार्जिन पर विचार करके सभी संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन किया है। प्राधिकारी ने आवेदकों के दावे की जांच की और यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद है।

निर्यात कीमत

7. आवेदक ने भारत में आयातों की मात्रा एवं मूल्य का आकलन करने के लिए डी जी सी आई एंड एस के प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्यात कीमत का दावा किया है। समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय भाड़ा व्यय तथा बैंक प्रभारों के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं। संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत का पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद है।

पाटन मार्जिन

8. आवेदक ने पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए इस बात का पर्याप्त प्रमाण दिया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

9. आवेदक ने दावा किया है कि उसे वास्तविक क्षति हुई है और उसने आयातों में समग्र रूप में हुई वृद्धि, उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग में आई गिरावट, लाभ, लगाई गई पूंजी पर आय और नकद लाभ आदि में कमी के रूप में संबद्ध देशों से आरोपित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत किया है। आवेदक ने कीमत ह्रास और कीमत कटौती के कारण प्रतिकूल कीमत प्रभावों का भी दावा किया है। प्राधिकारी का विचार है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात द्वारा आवेदक को 'क्षति' पहुंचने का पर्याप्त प्रमाण है अतः पाटनरोधी जांच आरंभ करना न्यायोचित होगा।

जांच की शुरुआत

10. प्राधिकारी ने यह पाया है कि पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की और वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को 'क्षति' और पाटन और 'क्षति' के बीच कारणात्मक संबंध का पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य है। प्राधिकारी किसी आरोपित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की उस राशि, जिसे यदि लागू किया जाएगा तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने हेतु आरोपित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति के बारे में एतद्वारा पाटनरोधी नियमों के नियम 5 के अनुसार जांच आरंभ करते हैं।

जांच की अवधि

11. वर्तमान जांच हेतु जांच अवधि 1 जनवरी, 2012 से दिसम्बर 2012 तक होगी। तथापि क्षति जांच अवधि में अप्रैल 2009—मार्च, 2010, अप्रैल 2010—मार्च, 2011, अप्रैल 2011 से मार्च 2012 की अवधि और जांच अवधि (पीओआई) शामिल होगी।

सूचना प्रस्तुत करना

12. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों और भारत में स्थित दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबंधित समझे गए आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में तथा निर्धारित ढंग से समस्त सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संबंधित अनुरोध नीचे निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत कर सकता है और निम्नलिखित को लिख सकता है:

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

कमरा सं0 240, उद्योग भवन,

नई दिल्ली - 110107

समय सीमा

13. इस जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित में भेजी जानी चाहिए जो प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिन के भीतर पहुंच जानी चाहिए। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त

नहीं होती है अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

14. पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(1) के अनुसार प्रदान की गई गोपनीय सूचना हेतु पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा एक गोपनीय तथा अगोपनीय सार प्रस्तुत किया जाएगा। गोपनीय सूचना का अगोपनीय रूपान्तर या अगोपनीय सारांश पर्याप्त रूप से विस्तृत होना चाहिए जिससे कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सूचना की एक सार्थक समझ प्रदान की जा सके। यदि सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विचार में ऐसी सूचना का सारांश तैयार नहीं किया जा सकता है तो उसके कारणों का विवरण प्रदान करना अपेक्षित होगा।

15. उपर्युक्त पैरा में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता हेतु अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता या तो सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य अथवा सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह इस तरह की सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

16. नियम 8(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपान्तर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

असहयोग

17. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं करता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे. एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

New Delhi, the 7th May, 2013

INITIATION NOTIFICATION

Subject: Initiation of Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of "Phenol" originating in or exported from Chinese Taipei and USA.

No.14/17/2012-DGAD : M/s Hindustan Organic Chemicals Limited (hereinafter referred to as 'petitioner' or "the applicant") has filed an application (also referred to as petition) before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) for initiation of Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of Phenol (hereinafter also referred to as the subject goods) originating in or exported from Chinese Taipei and USA (hereinafter also referred to as the subject countries). M/s Hindustan Organic Chemicals Limited has provided relevant information.

Product under consideration

2. The product under consideration in the present petition and proposed investigation is "Phenol". Phenol is a basic organic chemical normally classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act. The product is marketed in two forms – bulk and packed. Bulk sales are normally in loose form, whereas packed consignments can be of much smaller container loads and generally packed in drums. Phenol is used in Phenol Formaldehyde Resins, Laminates, Plywood, Particle Boards, Bisphenol-A, Alkyl Phenols, Pharmaceuticals, Diphenyl Oxide etc. This product is classified under Customs Tariff heading no. 29071110.

However, the said Customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

Like Articles

3. The applicant has claimed that the subject goods, which are exported from subject countries into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. Phenol produced by the domestic industry and imported from subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the AD Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India is being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

Domestic Industry & Standing

4. The application has been filed by M/s Hindustan Organic Chemicals Limited. Another domestic producer M/s SI group has supported the application. It is noted that the applicant and supporter accounts for total Indian production of subject goods in the country. It is also noted that the production by the petitioner constitutes a major proportion in total production of the like product produced in India. It is also noted that petitioner has not imported the product under consideration, nor are they related to an importer or exporter of the product under consideration. It is thus determined that the application has been made by or on behalf of the domestic industry and the application satisfies the requirements of 'standing' under Rule 5 of the AD Rules. Further, the Applicant constitutes 'Domestic Industry' in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.

Subject Countries

5. The countries involved in the present investigation are Chinese Taipei and USA.

Normal value

6. The Petitioner has submitted that efforts were made to get information/evidence of price of subject goods in the domestic market of subject countries. However, petitioner was not able to get such information. The petitioner has therefore constructed normal value for all subject countries taking into account international raw material price, best consumption norm of domestic industry and reasonable profit margin. The Authority examined the claim of the petitioner and notes that there is sufficient prima facie evidence of normal value of the subject goods in the subject countries.

Export Price

7. The applicants have claimed export price for product under consideration based on DGCI&S published data to assess the volume and value of imports in India. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, inland freight expenses and bank charges. There is sufficient prima facie evidence of export price of the subject goods in the subject countries.

Dumping Margin

8. The applicant has provided sufficient evidence that the normal values of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the net export prices, prima-facie indicating that the subject goods originating in or exported from the subject countries are being dumped, to justify initiation of an anti-dumping investigation.

Injury and Causal Link

9. The applicant has claimed that they have suffered material injury and have furnished evidence regarding injury having taken place as a result of the alleged dumping from subject countries in terms of increase in imports in absolute terms, decline in production, sales, capacity utilization, deterioration in profits, return on capital employed and cash profit etc. The applicant has also claimed adverse price effects as evidenced by price suppression and price undercutting. The Authority considers that there is sufficient evidence of 'injury' being suffered by the applicant caused by dumped imports of subject goods from subject countries to justify initiation of an anti-dumping investigation.

Initiation of Investigations

10. The Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, 'injury' to the domestic industry and causal link between the dumping and 'injury' exist to justify initiation of an anti-dumping investigation. The Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

Period of Investigation

11. The period of investigation for the present investigation is from 1st January, 2012 to December 2012. However, the injury investigation period will cover the periods April 2009-March 2010, April 2010-March 2011, April 2011 to March 2012 and the Period of Investigation (POI).

Submission of information

12. The known exporters in the subject countries and their Governments through their Embassies in India, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time-limit set out below and write to:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce
Room No.240, Udyog Bhawan,
New Delhi -110107.

Time limit

13. Any information relating to this investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of publication of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the 'facts available' on record in accordance with the AD Rules.

Submission of Information on Non-Confidential basis

14. All interested parties shall provide a confidential and non-confidential summary in terms of Rule 7 (2) of the AD Rules for the confidential information provided as per Rule 7 (1) of the AD Rules. The non-confidential version or non-confidential summary of the confidential information should be in sufficient detail to provide a meaningful understanding of the information to the other interested parties. If in the opinion of the party providing information, such information is not susceptible to summary; a statement of reason thereof is required to be provided.

15. Notwithstanding anything contained in para above, if the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, it may disregard such information.

Inspection of Public File

16. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

17. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

J. S. DEEPAK, Designated Authority

1875 GZ/13-2